# ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा


पेजः 4

**कार्बन डाइ आक्साइड उत्सर्जन में पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल**

रविवारीय, 03 - 09 जनवरी 2021 वर्ष- दो, अंक-22, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपया


ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

### भारतीय इतिहास का आठवां सबसे गर्म वर्ष रहा 2020

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चला है कि 2020 भारतीय इतिहास का आठवां सबसे गर्म वर्ष था। इस वर्ष तापमान सामान्य से 0.29 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। हालांकि यदि वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि की बात करें तो 2020 का औसत तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था।

गौरतलब है कि 2016 में अब तक का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था। जब तापमान 1980 से 2010 के औसत की तुलना में 0.71 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि जलवायु में आ रहे बदलावों के चलते देश में तापमान लगातार बढ़ रहा है। अब तक के 12 सबसे गर्म वर्ष हाल के पंद्रह वर्षों (2006 से 2020) के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे। इसी तरह यदि अब तक के सबसे पांच गर्म वर्षों की बात करें तो 2016 पहले स्थान पर था जब तापमान सामान्य से 0.71 डिग्री सेल्सियस अधिक था।

देश अभी कोरोना महामारी से निबट ही रहा है कि इसी बीच केरल से लेकर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में पक्षियों की मौत से

# अब बर्ड फ्लू की दस्तक

मुख्य संवाददाता

देश अभी कोरोना के खतरे से उबरने की कोशिश ही कर रहा है कि इसी बीच कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। पिछले 10 दिनों में भारत के कई राज्यों में लाखों पक्षी मृत मिले हैं। कम से कम चार राज्यों- हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान ने बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई अन्य राज्य भी अलर्ट हो गए हैं। केरल में पिछले कुछ दिनों में 12,000 बत्तखों की मौत हुई है, जिसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु सावधानी बरत रहे हैं। वहीं हिमाचल में भी हजारों पक्षी मृत मिले थे, जिस-के बाद जम्मू-कश्मीर और हरियाणा ने अपने-अपने राज्य में सैंपलों की जांच करनी शुरू कर दी है। बता दें कि बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू वायरस घरेलू पोल्ट्री और दूसरे पक्षियों और जानवरों की नस्लों को संक्रमित कर सकता है

### कोरोना से ज्यादा घातक

बर्ड फ्लू वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे संक्रमित लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. जबकि, कोरोना से संक्रमित लोगों में से मरने वालों की दर करीब 3 फीसदी है. इसलिए बर्ड फ्लू को लेकर देश के कई राज्य अलर्ट हो चुके हैं. राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे बर्ड फ्लू पर नज़र रखी जा रही है.

### झारखंड में कितना है खतरा?

राज्य में सैकड़ो बड़े डैम और झीलें हैं पतरातू डैम तिलैया डैम जिनमें प्रवासी पक्षियों की भरमार हो जाती है और जाड़े में लोग इन्हें देखने भी आते हैं। यहां भी प्रवासी पक्षियों के माध्यम से बर्ड फ्लू फैलने की आशंका सदैव बनी रहती है।

पिछले वर्ष ओरमांझी के जैविक उद्यान में कई पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। लेकिन सौभाग्य से इसका फैलाव नहीं हुआ और समय रहते इसे नियंत्रित कर लिया गया।यहां इसका फैलाव अनियंत्रित हुआ तो पोल्ट्री उद्योग के भयंकर नुकसान के साथ ही लोगों के जान पर भी आफत बन आयेगी।

वर्तमान खतरे को देखते हुये मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स बनाने बात कही है, वहींराज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि बर्ड फ्लू के चलते राज्य में अतिरिक्त एहतियात बरता जा रहा है। झारखंड को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि वृहत पैमाने पर समीक्षा के उपरांत और भी सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल सीमा सील करने जैसी स्थिति नहीं है। सभी जिला उपायुक्तों को पैनी निगाह रखने का निर्देश दिया गया है।

**बेहतर हो कुछ दिन चिकेन अंडे जैसी चीजों से दूर ही रहें**



● केरल में अलप्पुझा और कोट्टायम के कई हिस्सों में एवियन इंफ्लुएंज़ा का स्ट्रेन मिलने के बाद यहां पर लगभग 36,000 पक्षियों को मारे जाने की संभावना है. दो जिलों में यह काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। दो जिलों में कंट्रोल रूम और क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाए गए हैं। वनमंत्री के राजू ने इस हफ्ते बताया था कि पोल्ट्री मालिकों को मुआवजा दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा।

● हरियाणा के पंचकूला में पिछले 10 दिनों में चार लाख पोल्ट्री के पक्षियों की मौत हुई है। हालांकि, राज्य ने अभी तक फ्लू की पुष्टि नहीं की है। प्रशासन का कहना है कि इसकी जांच हो रही है।

● हिमाचल प्रदेश ने मंगलवार को राज्य में एवियन फ्लू होने की पुष्टि की। यहां पर माइग्रेट करके आने वाले गीज़ की एक नस्ल के लगभग 2,700 पक्षी मृत मिले थे। हिमाचल के कांगड़ा में किसी भी तरह के पोल्ट्री के पक्षियों, किसी भी नस्ल की मछलियां या उनसे जुड़ा उत्पाद, जिसमें अंडा, मीट, चिकन वगैरह शामिल है, के स्लॉटर, खरीद-बिक्री और निर्यात पर रोक लग गई है।

● मध्य प्रदेश में 300 कौवों की मौत से बर्ड फ्लू का खतरा पैदा हो गया है। इंदौर और मंदसौर से लिए गए कुछ सैंपल्स में की मौजूदगी की पुष्टि की है। बर्ड फ्लू को लेकर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। मंत्री विश्वास सारंग, सीएस, पीएस मनीष रस्तोगी, मोहम्मद सुलेमान सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। भारत सरकार द्वारा भेजी गई गाइडलाइन पर चर्चा हो रही है। पोल्ट्री फार्म मालिकों को निर्देश दिए जाएंगे और पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के सैंपल लिए जाएंगे। इंदौर में अचानक हुई कौवों की मौत देखते हुए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और रैपिड रिस्पान्स टीम एक्शन में आ गई है। कोविड से लड़ रहा स्वास्थ्य विभाग यहां पर लोगों को डोर-टू-डोर मेडिकल चेकअप कर रहा है।

● राजस्थान के पशुपालन मंत्री लाल चंद कटारिया के हवाले से बताया कि राजस्थान के झालवार, कोटा और बारण में पक्षियों में वायरस मिला है। मंगलवार तक यहां 16 जिलों में 625 पक्षियों की मौत हो चुकी है।

● महाराष्ट्र ने अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं किया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने भी नई दिल्ली में राज्य सरकारों के एक्शन और पूरे मामले की मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है।देश के सभी राष्ट्रीय अभ्यारण्यों और पार्कों को सावधानी बरतने को कहा गया है।

बॉक्साइट खनन से सूख रही छत्तीसगढ़ और झारखंड की बुढ़ा नदी

# भेड़ियों के एक मात्र ठिकाने पर खतरा

एजेंसियांः छत्तीसगढ़ और झारखंड में बॉक्साइट का खनन बड़े पैमाने पर होता है। स्थानीय पर्यावरण को इससे काफी नुकसान हो रहा है। झारखंड स्थित भेड़िया अभयारण्य भी इस बॉक्साइट खनन से काफी प्रभावित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में खनन की वजह से बुरहा नदी में पानी कम हो रहा है। नुकसान देखते हुए झारखंड स्थित खदान को बंद कर दिया, लेकिन इससे सटे छत्तीसगढ़ के खदान अभी चालू हैं। दो राज्य का मामला होने की वजह से कोई समुचित समाधान नहीं निकल पा रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग आरोप लगाते हैं कि धूल से उनके खेत खराब हो रहे हैं और खेती तबाह हो रही है।

छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बॉक्साइट की खनन की वजह से देश के एक मात्र भेड़िया अभ्यारण्य के लिए खतरा उत्पन्न होने लगा है। चमकते एल्युमीनियम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस खनिज के खनन से स्थानीय बुढ़ा नदी भी प्रभावित हो रही है।

एल्युमीनियम का एक प्रमुख स्रोत बॉक्साइट है। धूल में लिपटे सुर्ख या गुलाबी मिट्टी जैसे छोटे-बड़े टुकड़ों से इसे निकाला जाता है। इसमें 28 से 80 प्रतिशत तक एल्युमीनियम ऑक्साइड (एल्युमिना) होता है, जिसकी वजह से यह एल्युमीनियम का सबसे लोकप्रिय स्रोत माना जाता है। देश में इस बॉक्साइट के सबसे अधिक खदान झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक झारखंड में बॉक्साइट 68,135 हजार टन और छत्तीसगढ़ में 16 .8 करोड़ टन है। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण खनिज है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के खनिज समृद्धि में इसका विशेष योगदान है। हालांकि, बॉक्साइट खनन का स्याह पक्ष भी है। इससे स्थानीय पर्यावरण प्रभावित होता है। दोनों राज्यों में बहने वाली बुढा नदी पर पड़ने वाला असर, इसका एक उदाहरण है। झारखंड स्थित देश के इकलौते महुआडांड भेड़िया अभ्यारण्य पर भी खनन का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है।

लातेहार स्थित ओरसा गांव में बॉक्साइट खनन की शुरुआत वर्ष 1986 में हुई थी। तब भेड़िया अभयारण्य से खदान 2 .5 किलोमीटर दूर हुआ करती थी और यह 309 .36 हेक्टेयर में फैली थी। यहां खनन के लिए लीज 2006 तक ही जारी हुआ था, लेकिन बाद में (2017) 196 हेक्टेयर जमीन पर 2036 तक के लिए खनन की अनुमति दे दी गयी। ....शेष पेज 4 पर

# थाइलैंड में दिखेगी झारखण्ड के 'जावा परब नृत्य' और 'छऊ नृत्य ' की पेंटिंग

सिदाम महतो

रांचीः-थाइलैंड में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन 'विजन2021' में झारखंड की संस्कृति को जगह मिली है। छोटानागपुर कुड़मि कला जगत के महावीर महतो की दो पेंटिंग का चयन इस पेंटिंग प्रदर्शनी में हुआ है। उनकी एक पेंटिंग में जावा नृत्य को दिखाया गया है और दूसरी पेंटिंग में छोऊ नृत्य के मोहड़ा(मुखोटा) । झारखंड के लिए यह गर्व की बात है।

**क्या है जावा परब?**

भादो माह के शुल्क पक्ष में करम परब के सात दिन पहले झारखंड आदिवासी समाज की बेटियां नदी जाकर बांस की डाली में बालू भरकर उसमें धान, चना, जौ, कुरथी, मुंग, उरद सहित नौ प्रकार के अनाज के दानों को डालती है। इसके बाद नदी से करमा गीत गाते -गाते डाली को घर लाती है। सात दिन सुबह-शाम इस पर हल्दी लगा जल डालती है। इसको बीच में रखकर चारों ओर नृत्य करती है। सात दिन तक में यह अंकुरित होता है। इसे जावा कहते हैं। और इस नृत्य को जावा नृत्य कहते हैं। जावा के अंकुरण को सृजन का





प्रतीक माना जाता है। झारखण्ड की पहचान छऊ नृत्य से भी है। यहां के कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है।

ऑनलाइन होने वाले इस अंतर-राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगता का आयोजन पॉजिटिव एनर्जी आर्ट के द्वारा थाइलैंड के शी-दीन-स्टूडियो और चारकोल फाउंडेशन के सहयोग से बोंगारा में किया जा रहा है। 5 जनवरी से 19 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में यूएस, मारीशस, थाईलैंड, नेपाल,बांग्लादेश, मोरोक्को, टर्की ,इटली,इजिप्ट,ईरान, इंडोनेशिया,यूएई, ब्राजील , नार्थ मेसोडोनिया, साउथ अफ्रीका, कोसोवो,ट्यूनेशिया,रशिया, निगेर्य, गियोरिर्ग, सेनेगल, श्रीलंका, सेरेबिया, सूडान, भारत आदि देश सम्मिलित है। भारत से कई प्रतिभागियों के पेंटिंग का चयन इस प्रदर्शनी में हुआ है। उसमें से एक धनबाद , निवासी महावीर महतो की पेंटिंग भी है। इस चयन में महावीर ने खुशी जाहिर की है। वे कहते हैं झारखंड की संस्कृति को पेंटिंग के माध्यम से विश्व पटल पर जाना , बहुत खुशी हो रही है।

महावीर महतो वर्तमान में जूनागढ़ गुजरात के स्कूल में आर्ट शिक्षक हैं।

# सीसीएल सीएमडी ने नववर्ष की बधाई दी

*सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने नये वर्ष में दरभंगा हाउस, रांची के स्वर्ण रेखा बिल्डींग, गोदावरी बिल्डींग, अलखनंदा बिल्डींग, दामोदर बिल्डींग, मेन बिल्डींग, न्यू बिल्डींग स्थित सतर्कता विभाग सहित सभी विभागों में जाकर कर्मियों से मिले और उन्हें नव-वर्ष की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल सहित महाप्रबंधक (प्रशासन) डॉ ए.के. सिंह एवं अन्य उपस्थित थे।*

# रोजगार | एक्वेरियम निर्माण- एक लाभकारी व्यवसाय

**आशीष कुमार**

रंगीन मछलियों के पालने के लिए एक्वेरियम आवश्यक है। इसे शीशे को जोड़कर आसानी से बनाया जा सकता है। यदि किसी एक्वेरियम बिक्री करने वाले व्यापारी से सम्पर्क है तो आसानी से एक्वेरियम की बिक्री की जा सकती है। इसके लिए शीशा चिपकाने वाला सिलिकॉन जेल और उसे निकालने वाले विशेष प्रकार के गन की आवश्यकता होती है। इसमें महत्वपूर्ण है कि किस आकार के एक्वेरियम का निर्माण करना है। सामान्यता डेढ़ फीट चौड़ा, डेढ़ फीट ऊंचा और 1 फीट लंबा



एक वरियम की मांग रहती है। तो उसी आकार का शीशा कटवा कर उसे जेल की सहायता से चिपका कर एक्वेरियम तैयार किया जा सकता है। इसके बाद आवश्यकता होगी उसके लिए ढक्कन की जो की लकड़ी, टीन या फाइबर का बनाया जा सकता है। इसके साथ ही एक्वेरियम रखने के लिए टेबल की आवश्यकता होगी जिसे अलग से बनवाना पड़ेगा। यदि एक्वेरियम, ढक्कन और टेबल की व्यवस्था हो जाए तो आसानी से एक्वेरियम के दुकानों को आपूर्ति की जा सकती है। जिसमें लागत कम लगती है और मुनाफे की संभावना अधिक है।

रंगीन मछली रखने के शौकीन लोगों की संख्या शहरों में खास करके धीरे-धीरे बढ़ रही है। ऐसे में यदि एक्वेरियम बनाकर आपूर्ति किया जाए तो अतिरिक्त आमदनी का एक साधन मिलेगा और रोजगार का सृजन होगा। यदि साथ में एक्वेरियम के सजावट की चीज है जैसे पत्थर खिलौने, एरेटर, पाइप इत्यादि भी आपूर्ति किए जाएं तो मुनाफा और बढ़ाया जा सकता है। सरकार के मत्स्य विभाग के द्वारा एक्वेरियम निर्माण और रंगीन मछली पालन का समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित होता रहता है जिसका लाभ उठाकर पढ़े लिखे नौजवान या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस व्यापार को अपनाकर लाभ कमा सकती हैं।


*लेखक सेवानिवृत उपनिदेशक (मत्स्य विभाग) हैं*

Ph. 9430783037

email:coomar2012@gmail.com

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा



# वैक्सीन पर बेवकूफी

भारत के वैक्सीन बनाने की क्षमता के सामने विश्व में कोई नहीं टिकता। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश तो कोरोना वैक्सीन के लिये भारत से पहले से ही खुशामद कर रहे हैं वहीं यूरोप और अमेरिका के देश भी भारत में वैक्सीन के निर्माण के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भारत में सब कुछ आसानी से संपन्न नहीं होता। किसी भी अच्छे काम में यहां हमेंशा से विघ्न बाधा की परंपरा रही है। सीरम इंडिया के अलावा सरकार ने भारत बायोटेक के वैक्सीन को भी आपातकालीन मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अनुमानतः बहुत सस्ती है और इसे बहुत ज्यादा शीतलक की आवश्यकता नहीं है। सरकार के इस मंजूरी के बाद देश में कुछ तबकों ने यह शोर करना शुरू कर दिया है कि यह वैक्सीन नहीं पानी है। ज्ञात हो कि भारत बायोटेक भी ढाई दशक पुरानी कंपनी है और उसका भी वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में अच्छा अनुभव है। उसने भी शोध और प्रयोग करके ही वैक्सीन बनायी होगी।

किसी और देश में भारत बायोटेक जैसी कंपनी ने वैक्सीन बनाया होता तो उसे और उत्प्रेरित किया जाता। कई मानकों पर जांचा जाता न कि उसे बेकार करार दिया जाता।

देश में दवाओं और वैक्सीन के बड़े बाजार से व्यावसायिक लाभ के लिये ऐसी मूर्खता भरी बातें अंततः आमजन पर ही भारी पड़ेगा। हमें यह समझना होगा कि प्रत्येक विदेशी या महंगी चीजे ही अच्छी नहीं होती और हम भारतवासियों को देश में शोध, आविष्कार को हमेंशा दुत्कारने की प्रवृत्ति से भी बाज आना होगा। आखिर हम चीन से घटिया उत्पाद लंबे समय तक खरीदते रहे और चीन को मजबूत बनाते रहे, तब हमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन आज देशी कंपनी ने एक सस्ता वैक्सीन बनाया तो बजाय उसे परखने के उसका उपहास करना बेवकूफी नहीं तो और क्या है?

*हम भारतीयों की एक बहुत ही ख़राब फितरत होती है कि वो सस्ते लेकिन कारगर उत्पादों पर जल्दी भरोसा नहीं करते। हम जब तक मोटी रकम लगाकर कोई चीज नहीं ख़रीदते तब तक हमें उसके अच्छे होने का भरोसा नहीं होता? कई बार तो हम देश में बनी वस्तुओं को सिर्फ इसलिये घटिया या गैरभरोसेमंद मान लेते हैं क्योंकि वह विदेश से बन कर नहीं आया है।*

*याद किजिये जेनेरिक दवाओं के मामले में भी प्रारंभ में आम भारतीय सशंकित था और सस्ते पर कारगर जेनेरिक दवाओं के प्रभावी होने पर शक कर रहा था। उस वक्त भी बहुत बवाल हुआ। ब्रांडेड दवाई माफियाओं ने भी खूब शोर किया कि ये दवायें बेकार हैं और मरीजों की जान के साथ यह खिलवाड़ हो सकता है, पर एक बार यह शक दूर होते हीं जेनेरिक दवाओं के काउंटर पर भीड़ उमड़ने लगी।*

*आज भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन के मामले में भी इसी संशय को दूर करने की आवश्यकता है। आखिर सारा विश्व भारत की ओर ही वैक्सीन के लिये देख रहा है।*

## जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर के शहरों में घट जाएगी नमी

शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के चलते वैश्विक स्तर पर शहरों के तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में छपे एक शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर के शहरों में नमी की मात्रा घट जाएगी। अनुमान है कि सदी के अंत तक यदि उत्सर्जन में वृद्धि जारी रहता है तो तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। शहर जोकि धरती के केवल तीन फीसदी हिस्से पर फैले हैं, पर उनमें विश्व की 50 फीसदी से ज्यादा आबादी रहती है, जो 2050 तक बढ़कर 70 फीसदी पर पहुंच जाएगी। एक ही जगह पर आबादी का जमावड़ा कई समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। इसमें गर्मी से बढ़ता तनाव, पानी की कमी, वायु प्रदूषण और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याएं प्रमुख हैं।

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के असर को समझने के लिए कई मॉडल विकसित किए गए हैं। इस शोध से जुड़े शोधकर्ताओं का मानना है कि उन मॉडलों को बड़े स्तर पर विश्लेषण करने के लिए तैयार किया गया है। इन्हें शहरों को ध्यान में रखकर नहीं तैयार किया गया है। लेकिन इस नए शोध में शोधकर्ताओं ने शहरों पर जलवायु परिवर्तन के असर को करीब से समझने के लिए पारम्परिक क्लाइमेट मॉडल के साथ-साथ आंकड़ों पर आधारित स्टैटिस्टिकल मॉडल का भी प्रयोग किया है। जिसे विशेष तौर पर शहरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता ली झाओ के अनुसार ''शहरों में सतह कंक्रीट और डामर की बनी होती है, जो कच्ची जमीन की तुलना में बहुत अधिक गर्मी को सोखती है और उसे बनाए रखती हैं। ऐसे में वातावरण बहुत तेजी से गर्म होता है और नमी खो देता है।'' ऊपर से घटते पेड़ इस हीट आइलैंड की समस्या को और बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि शहरों में तापमान कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि शहरों का तापमान अपने आस-पास के ग्रामीण इलाकों से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होता है।

# राजनीतिः अर्थव्यवस्था बनाम प्रदूषण

सुविज्ञा जैन

पर्यावरण को हो रहे नुकसान के कारण ही जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे वर्षाचक्र गड़बड़ा रहा है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के सिर पर पीने का पानी और पर्याप्त कृषि उपज का संकट मंडराने लगा है। अगर इसी तरह पर्यावरण तबाह होता रहा तो आगे चल कर एक आर्थिक दुर्घटना को टालना मुश्किल नजर आ रहा है।

वायु प्रदूषण पर चिंताओं का सिलसिला जारी है। देखा जाए तो कुछ ही साल से सिर्फ सर्दियों में ही वायु प्रदूषण की ज्यादा चर्चा होने लगी है। वरना पांच-सात साल पहले तक भारत में लगातार पूरे साल प्रदूषण पर चिंता जताई जा रही थी। सरकारों को पूरे साल याद दिलाया जाता था कि प्रदूषण से जान और माल दोनों का कितना नुकसान होता है। इधर विशेषज्ञ एक बार फिर बताने लगे हैं कि प्रदूषण के कारण हर साल न सिर्फ सत्रह लाख मौतें हो रही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को देश की जीडीपी का सात फीसद यानी लगभग चौदह लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है।

यह रकम वित्तीय घाटे की कमोबेश दुगनी बैठती है। गौर करने की बात है कि दुनिया में विकसित देश जब पर्यावरण से समझौता करते हैं तो यही कहते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था को पहले देखना है, बाकी बाद में। अब जब अपने देश में वायु प्रदूषण से देश को हर साल चौदह लाख करोड़ रुपए के नुकसान का आंकड़ा निकल कर आ रहा हो तो क्या इसका एक मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण से जान-माल का दोहरा नुकसान हो रहा है। अगर वित्तीय घाटा बढ़ना इतनी बड़ी चिंता की बात है तो प्रदूषण के कारण आर्थिक हानि की चिंता दुगनी बड़ी मानी जानी चाहिए।

कई शोध सर्वेक्षणों का निष्कर्ष है कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए कामगारों के छुट्टी पर जाने से हर साल पचास करोड़ श्रम दिवसों का नुकसान हो जाता है। वायु प्रदूषण से होने वाली तरह-तरह की बीमारियों के इलाज पर औसतन एक हजार नौ सौ रुपए प्रति व्यक्ति अलग से खर्च हो जाते हैं। यह आंकड़ा

2019-20 वित्तीय वर्ष का है। जबकि 2015 में यह खर्च एक हजार आठ रुपए प्रति व्यक्ति आंका गया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पांच साल के अंतराल में वायु प्रदूषण ने नागरिकों के कंधों पर स्वास्थ्य खर्च का कितना बोझ बढ़ा दिया है। क्या इस बात पर हैरत नहीं जताई जानी चहिए कि देश का सालाना स्वास्थ्य बजट सिर्फ उनहत्तर हजार करोड़ का है, लेकिन सिर्फ वायु प्रदूषण से होने वाला नुकसान चौदह लाख करोड़ है।

कहते हैं कि प्रदूषण के कारण मौतों और बीमारियों की त्रासदी से निपटने में इसी कारण दिक्कत है क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज्यादा खर्च करने की गुंजाईश नहीं निकलती। लेकिन जब प्रदूषण से सीधे-सीधे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने की बात बताई जा रही हो तो क्या हिसाब नहीं लगाया जाना चाहिए कि प्रदूषण को रोकने या कम करने का कितना खर्चा बैठेगा और उससे अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान कितनी मात्रा में रोका जा सकता है? बेशक प्रदूषण की चिंता करने से प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों पर लगाम लगानी पड़ती है। अर्थशास्त्री तर्क देने लगते हैं कि पहले आर्थिक विकास कर लिया जाए और फिर जो पैसा पैदा हो उससे प्रदूषण की समस्या से निपट लिया जाएगा।

नफे-नुकसान के आंकड़ों पर तफसील से बहस होनी चाहिए। बहुत संभव है कि यह पता चले कि पर्यावरण की कीमत पर पैदा होने वाली पूंजी आर्थिक विकास का छलावा है। प्रदूषण से होने वाले नुकसान की मात्रा बताई जाएगी तो बहुत संभव है कि यह सिद्ध हो जाए कि पर्यावरण से समझौता करके होने वाले औद्योगिक विकास से देश का आर्थिक विकास नहीं, बल्कि आर्थिक ह्रास हो रहा है। कम से कम वायु प्रदूषण से हर साल चौदह लाख करोड़ के नुकसान का आंकड़ा तो यही साबित कर रहा है। यहां बात भविष्य के मद्देनजर भी की जानी चाहिए।

आज का आर्थिक विकास अगर भविष्य की संभावनाओं को खत्म करता हो तो उसे खुद में एक हादसा कहा जाएगा। आज के अर्थशास्त्री सतत विकास की बात यों ही नहीं करते। वे आर्थिक विकास और सतत विकास का फर्क साफ-साफ समझा रहे हैं। बहरहाल, भविष्य को अगर वर्तमान में खाया जा रहा हो तो उस पर चिंता जताई ही जानी चाहिए। दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी ने सिद्ध कर दिया है कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान के कारण ही जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे वर्षाचक्र गड़बड़ा रहा है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के सिर पर पीने का पानी और पर्याप्त कृषि उपज का संकट मंडराने लगा है। अगर इसी तरह पर्यावरण तबाह होता रहा तो आगे चल कर एक आर्थिक दुर्घटना को टालना मुश्किल नजर आ रहा है। इसीलिए भविष्य के ऐसे नुकसान से बचने के लिए एक ही उपाय नजर आता है और वह यह कि पर्यावरण को ताक पर रख कर जो अंधाधुंध औद्योगिक विकास हुआ जा रहा है, उस पर अभी से लगाम लगे। अच्छी बात यह है कि दुनिया के कई उन देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने वक्त रहते पर्यावरण संरक्षण को अपनी पहली प्राथमिकता में शामिल किया। इन देशों में चीन भी है। उसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्यावरण के मामले में कुछ साल पहले बेजिंग की हालत भी दिल्ली जैसी हुई थी। तब वहां सबसे पहले अंधाधुंध औद्योगिक विकास को रोकना पड़ा था।

बाकायदा एक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्रवाई योजना बनाई गई। बेजिंग के आसपास कोयले से चलने वाले सारे बिजलीघर बंद करवा दिए गए थे। सड़कों पर बढ़ती निजी वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था पर ताबड़तोड़ सरकारी निवेश किया गया। उद्योग जगत को इस तरह के प्रोत्साहन पैकेज दिए गए, जिससे वे पर्यावरण अनुकूल कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित हों और साथ ही नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने लगाए गए। उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में कई ऐतिहासिक और केंद्रीय स्थानों पर वाहन ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई। निजी वाहनों के लिए सम-विषम का तरीका वहां कभी कभार नहीं, बल्कि नियमित रूप से प्रयोग में लाया जाता है। गौरतलब है कि प्रदूषण बढ़ने के अंदेशे वाले त्योहारों के दौरान यातायात के सरकारी साधनों को मुफ्त कर दिया जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 2025 तक कार्बन मुक्त बना देने का एलान कर दिया गया है। कोपेनहेगन के बारे में कहा जाता है कि वहां साइकिलों की संख्या उनकी आबादी से ज्यादा है। सरकारी यातायात की सुविधा बढ़ाने के पीछे का कारण भी वायु प्रदूषण से बचना रहा है। जर्मनी के फ्राईबर्ग शहर में तो सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बाइकवेज और ट्रामवेज बनवाए हैं।

जर्मनी के कुछ और अनुभव गौरतलब हैं। जैसे- फ्राईबर्ग में टोकन पद्धति का इस्तेमाल। वहां जिस व्यक्ति के पास डीजल या पेट्रोल का वाहन नहीं होता, उसे सस्ते मकान और सस्ती सरकारी यातायात सुविधा दी जाती है। वहां के पर्यावरण विशेषज्ञ और पर्यावरण कार्यकर्ता अपनी सरकार को समझाने में कामयाब रहे कि इन उपायों में उसका जो खर्च होगा, उससे वह घाटे में नहीं, बल्कि मुनाफे में रहेगी, क्योंकि पर्यावरण को पहुंचने वाला नुकसान आर्थिक विकास के फायदों से कहीं ज्यादा बैठ रहा है। इसी तरह नीदरलैंड में भी 2025 तक डीजल-पेट्रोल के वाहन पूरी तौर पर खत्म करने की योजना है। आने वाले दिनों में नीदरलैंड में सिर्फ हाइड्रोजन और बिजली से चलने वाले वाहन ही खरीदे जा सकेंगे। फिनलैंड, स्विटजरलैंड, ब्राजील जैसे कई देशों ने जन यातायात को बेहतर बनाने का काम अपनी प्राथमिकता में रखा है और इसमें भारी निवेश किया है तो उसके पीछे मुख्य मकसद प्रदूषण से बचाव का ही है।

लगभग सभी उदाहरणों में सबसे गौरतलब नुक्ता यही है कि जिन देशों ने भी पर्यावरण के मामले में बड़ी मंजिलें हासिल की हैं, वे आर्थिक विकास से समझौता करने के बाद ही हासिल कर पाई हैं। हम भी अभी अपनी आर्थिक मजबूरियों का तर्क देकर भले ही इस बात को न मानें, लेकिन देर-सबेर हमें दूसरे देशों के सबक लेने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा।

# फूलों की खेती में है खुशबू बिखेरने की अपार क्षमता

*सुरिंदर सूद*

सन 1988 में बीज नीति को उदार बनाए जाने के बाद सन 1990 के दशक के आरंभ में देश में फूलों की व्यावसायिक खेती की शुरुआत हुई थी। इतना समय बीत जाने के बाद अब फूलों की खेती, कृषि जगत के बागवानी क्षेत्र का एक विशिष्ट और आकर्षक हिस्सा बन चुकी है। बीते दो दशक में इस क्षेत्र की वृद्धि वाकई उल्लेखनीय है। सन 2001 से अब तक फूलों की खेती का रकबा 4.4 गुना बढ़ा है और उत्पादन में 5.6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। घरेलू स्तर पर इन फूलों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसकी अधिकांश खपत भी घरेलू बाजार में हो जाती है लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र को निर्यात की दृष्टि से एक उभरते संभावनाशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। शादी समारोह, वर्षगांठ, वैलेन्टाइंस डे, शिक्षक दिवस, मातृ दिवस, क्रिसमस, नव वर्ष तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर तोहफे में फूल देने का चलन भी बढ़ा है।

करीब 28.6 लाख टन के सालाना उत्पादन के साथ भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुष्प उत्पादक देश है। पहले स्थान पर अब भी चीन कायम है। दूसरे स्थान पर पहुंचने की इस उल्लेखनीय यात्रा में भारत ने नीदरलैंड, विभिन्न यूरोपीय देशों तथा अमेरिका जैसे मुल्क को पीछे छोड़ा है। यद्यपि भारत में उपजे फूल दुनिया के 130 देशों में पहुंचने लगे हैं लेकिन फूलों की खेती से उपजे उत्पादों के निर्यात का बाजार का अभी गति पकडना शेष है। वैश्विक पुष्प व्यापार में भारत की हिस्सेदारी काफी कम करीब 0.4 फीसदी है। हालांकि भारत को भौगोलिक और जलवायु संबंधी लाभ हासिल है और दुनिया के कई बड़े देशों में जब फूलों की मांग चरम पर होती है, उस समय भारत में उत्पादन भी जोरों पर होता है। इस समय हम प्रति वर्ष 450 करोड़ रुपये से 600 करोड़ रुपये मूल्य के फूलों का

निर्यात करते हैं। ताजा आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि सन 2018-19 में हमने 571 करोड़ रुपये मूल्य का पुष्प संबंधी निर्यात किया जो इससे पिछले वर्ष के 507 करोड़ रुपये से 12.6 फीसदी अधिक था। सन 2019-20 में दिसंबर 2019 तक 445.48 करोड़ रुपये मूल्य के पुष्प उत्पादों का निर्यात किया गया था। बीते तीन वर्षों में अमेरिका भारत के फूलों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। इसके बाद जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इटली का नंबर आता है।

दिलचस्प बात यह है कि भारत में फूलों की खेती में अभी भी खुले खेतों में होने वाली फूलों की खुदरा खेती का दबदबा है। धार्मिक स्थानों के आसपास यह खेती ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान करते हैं क्योंकि वहां साल के अधिकांश समय मांग बरकरार रहती है। इन फूलों में व्यापक तौर पर गेंदा, गुलाब, बेला-चमेली, गुलदाउदी, गैलार्डिया, क्रॉसैंड्रा आदि की हिस्सेदारी 98 फीसदी है और फूलों की खेती में इन्हीं का दबदबा है। इन फूलों का अधिकांश कारोबार थोक में होता है और इनका इस्तेमाल हार बनाने, सामाजिक समारोहों की सजावट करने और धार्मिक स्थानों पर होता है। इनमें से कई का वाणिज्यिक इस्तेमाल भी होता है, मसलन तेल निकालने और गुलकंद जैसे पारंपरिक उत्पाद तैयार करने में। कई पुष्प औषधीय और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं।

आर्थिक उदारीकरण के बाद कॉर्पोरेट जगत के प्रवेश ने ही देश में फूलों की खेती को तकनीक सक्षम बनाया और तभी निर्यात गुणवत्ता वाले फूलों का उत्पादन भी शुरू हुआ। इन्हें ग्रीनहाउस में नियंत्रित वातावरण में तैयार करने की शुरुआत भी तभी हुई। इन कंपनियों ने प्रमुख तौर पर उन फूलों की खेती पर ध्यान दिया जिनकी वैश्विक बाजारों में अधिक मांग है। उदाहरण के लिए गुलाब, गुलनार, गुलदाउदी, जरबेरा, लिलियम, चाइना एस्टर आदि। विभिन्न प्रकार के ऑर्किड और एंथुरियम जो देश के पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में पाए जाते हैं, उन्होंने भी विश्व बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है। पुणे स्थित पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय के प्रमुख के वी प्रसाद के मुताबिक इन निर्यात आधारित पुष्पों में अधिकांश की उत्पादन इकाइयों ने नीदरलैंड, फ्रांस और इजरायल जैसे देशों से तकनीक हासिल कर उत्पादन कार्य शुरू किया लेकिन अब वे काफी हद तक स्वदेशी तकनीक पर स्थानांतरित हो गए हैं। ये स्वदेशी तकनीक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गई हैं। पुष्प विज्ञान क्षेत्र में आगे का काफी विकास स्थानीय तकनीकों के माध्यम से हो रहा है। सरकार भी जरूरी नीतिगत संरक्षण मुहैया करा रही है। वह कहते हैं कि किसानों और उद्यमियों की भूमिका भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है।

यह सही है कि वर्ष 2018-19 में फूलों की खेती का रकबा करीब 3.13 लाख हेक्टेयर था लेकिन इसमें काफी विस्तार की संभावना है। घरेलू और निर्यात संबंधी मांग में लगातार इजाफा होने के कारण इसके रकबे में तेज इजाफा हो सकता है और फूलों की खेती नए क्षेत्रों में विस्तार पा सकती है। हालांकि कुछ बाधाएं और चुनौतियां भी हैं जिन्हें हल करके इस क्षेत्र की संभावनाओं का अच्छी तरह दोहन किया जा सकता है। वैश्विक मांग और आपूर्ति को लेकर बाजार समझ की कमी और कीमतों को लेकर सही अनुमान नहीं लगा पाना भी ऐसी ही कमियां हैं। इसके अलावा चीन तथा पड़ोसी मुल्कों से भी इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मिल रही है। नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान भारत के पुष्प निर्यात के लिए चुनौती बनकर उभरे हैं। भारत की तरह इन देशों को भी जलवायु संबंधी लाभ हासिल है और वे बड़े आयातक देशों के लिए उस समय वे फूल उत्पादित कर रहे हैं जो आयातक देशों में कड़ाके की ठंड के कारण नहीं उग पाते। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह तकनीकी श्रेष्ठता के दम पर इन देशों पर बढ़त कायम करे। ऐसे में देश का पुष्पविज्ञान शोध नेटवर्क मददगार साबित हो सकता है

### मिट्टी की नमी से सूखे क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ता है

अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी की नमी में जलवायु परिवर्तन के कारण पर्याप्त गिरावट आने का अनुमान है। भविष्य में पानी की उपलब्धता में होने वाले बदलावों से दुनिया भर में ताजे पानी, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की स्थिरता के लिए बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। वर्षा और वाष्पीकरण में परिवर्तन विशेष रूप से सूखी जमीन (ड्राईलैंड) के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें वनस्पति का विकास और इसके नष्ट होने की दर काफी हद तक जल की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक जल चक्र तेज होने की उम्मीद है, लेकिन सतह के पानी की उपलब्धता में वाष्पीकरण के कारण बदलाव होगा।

ग्लोबल वार्मिंग से सतही जल की उपलब्धता बदल जाती है, नम क्षेत्रों में वर्षा से वाष्पीकरण द्वारा उत्पन्न ताजे पानी के संसाधनों में वृद्धि होगी और शुष्क क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता घटेगी। यह अपेक्षा मुख्य रूप से वायुमंडलीय थर्मोडायनामिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। जैसे ही हवा का तापमान बढ़ता है, समुद्र और भूमि से हवा में अधिक पानी वाष्पित हो जाता है। क्योंकि गर्म हवा शुष्क हवा की तुलना में अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है, पानी की उपलब्धता के मौजूदा पैटर्न को बढ़ाने के लिए एक अधिक नमी वाले वातावरण की आवश्यकता होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूखे क्षेत्र और सूखे होते जाएंगे और नमी वाली जगह और नम हो जाएगी।

### औसत से 109 फीसदी ज्यादा हुई 2020 में बारिश

यदि आंकड़ों पर गौर करें तो 2020 में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की थी। इस वर्ष सामान्य से 109 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। यह 1994 के 112 फीसदी एलपीए और 2019 के 110 फीसदी एलपीए के बाद तीसरा सबसे अधिक औसत था। इस बार देश में मानसून ने सामान्य से 12 दिन पहले ही दस्तक दे दी थी।

गौरतलब है कि 2020 में 26 जून तक मानसून देश के सभी हिस्सों में पहुंच चुका था, जोकि इसकी सामान्य तिथि (8 जुलाई) से 12 दिन पहले था। इस वर्ष यदि मानसून (जून से सितम्बर) की बात करें तो बारिश औसत से 109 फीसदी ज्यादा थी। इसी तरह मध्य भारत में औसत से 115 फीसदी, दक्षिण प्रायद्वीप में 129 फीसदी और पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में 106 फीसदी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में औसत का केवल 84 फीसदी बारिश हुई थी।

# इलेक्ट्रिक कारों को लाकर उत्सर्जन में कमी लाना है मुख्य लक्ष्य

*एजेंसियां*

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वर्ष 2021 की पहली छमाही में अमेरिका में डिजाइन की गई टेस्ला इलेक्ट्रिक कार भारत में उपलब्ध होगी। गडकरी ने कहा कि शुरुआत में पूरी तरह तैयार कार आयात की जाएगी, इसके बाद आंशिक रूप से तैयार कार भारत में आएगी तथा आखिर में इस कार को पूरी तरह भारत में ही निर्मित किया जाएगा। हालांकि बाद वाली परिस्थितियां तैयार होने में अभी वक्त लग सकता है। उनका होना न होना इस बात पर तो निर्भर करेगा ही कि शहरी भारत में टेस्ला को लेकर कैसी मांग नजर आती है लेकिन वह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कैसा नियामकीय माहौल तैयार होता है। यह बात ध्यान देने लायक है कि इलेक्ट्रिक वाहन मौजूदा सरकार की नई औद्योगिक नीति का अहम घटक हैं। इसके बावजूद देश में कम उत्सर्जन वाला परिवहन क्षेत्र विकसित करने के लिए अभी जो कुछ किया जा रहा है उससे अधिक कदम

उठाने की आवश्यकता होगी। फिलहाल जो योजनाएं हैं वे इस उभरते क्षेत्र के लिए बस बुनियादी प्रोत्साहन प्रदान करने वाली हैं। अलग कर या सब्सिडी की व्यवस्था पर सरकार पहले ही ध्यान दे चुकी है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को शहरी इलाकों में सहायक बुनियादी ढांचे के लिए अधिक स्थायी और सतत निवेश की दरकार है। उदाहरण के लिए इन्हें चार्जिंग स्टेशन ओर विशेष पार्किंग की आवश्यकता होगी। सरकार ने देश भर में 70,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना की घोषणा की है और कॉर्पोरेट जगत ने भी इसमें रुचि दिखाई है। यह बात ध्यान देने लायक है कि शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश काफी विवाद का विषय हो सकता है। यहां कुछ अलग सोच की आवश्यकता होगी। शायद एक विशेष कंपनी बनाना बेहतर हो जिसमें आधी हिस्सेदारी केंद्र सरकार की हो और आधी निजी क्षेत्र की। यह कंपनी विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए भूमि बैंक तैयार कर सकती है और बाद में इन्हें लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं या इनकी नीलामी की जा सकती है। इस व्यापक बुनियादी ढांचा विकास के लिए पहले से तैयारी रखनी होगी ताकि इसे किफायती और पारदर्शी बनाया जा सके।

इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भारत में कुछ विशिष्ट दिक्कत हैं। मिसाल के तौर पर बिजली की आपूर्ति में निरंतरता, गुणवत्ता, कीमत और उपलब्धता पर सवाल रहेंगे। यदि उपभोक्ताओं को यह आशंका होगी कि उनकी महंगी गाडिय़ां वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होंगी या बैटरी की कीमत एक ही शहर के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग होगी तो उन्हें परेशानी होना तय है। देश के कई हिस्सों में अभी भी चौबीस घंटे बिजली की उपलब्धता नहीं है। हालांकि इन आशंकाओं के बावजूद इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की तादाद लगातार बढ़ी है लेकिन उनकी कीमत अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों से एकदम अलग है और उनके मालिकों की जरूरतें और आदतें भी एकदम अलहदा हैं। अहम बात यह है कि कई पुराने कार निर्माताओं ने इस बात पर ध्यान दिया है कि पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की नीति भारत के लिए उपयुक्त नहीं भी हो सकती।

सरकार को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि उसका वास्तविक लक्ष्य परिवहन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन में कमी करना, हवा की गुणवत्ता में सुधार करना और ऊर्जा के क्षेत्र में स्वायत्तता हासिल करना है। निजी चार पहिया वाहन क्षेत्र को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करना, इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका भर है और जरूरी नहीं कि यह श्रेष्ठ भी हो। कुछ कार निर्माता हाइब्रिड कारों के लिए प्रोत्साहन चाहते हैं। सरकार को ऐसे प्रोत्साहन पर विचार करना चाहिए जो हर तरह की कार के उत्सर्जन प्रभाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो।

### हरियाणा में चार लाख से अधिक मुर्गियों की मौत, बर्ड फ्लू की आशंका

*चिकन या अंडे खाने को लेकर हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी की*

राजस्थान और हिमाचल में पक्षियों के मौत के बाद हरियाणा में भी रहस्यमय तरीके से मुर्गियों की मौत हो रही है। बीते दस दिनों में हरियाणा के पंचकूला जिले के बरवाला क्षेत्र में करीब चार लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है। मुर्गियों के मौत का कारण बर्ड फ्लू माना जा रहा है, लेकिन अधिकारिक तौर पर गुरुवार सुबह तक पुष्टि नहीं हुई थी। लगतार मुर्गियों के मौत होने के बाद हरियाणा पशुपालन और डेयरी विभाग ने चिकन या अंडे खाने को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए अच्छी तरह पकाकर खाने और पॉल्ट्री फॉर्म के अंदर नहीं जाने की सलाह दी है।

बुधवार को भी गांव गढ़ी कुटाह और गांव जलोली के पॉल्टी फार्म में करीब 20 हजार मुर्गियों की मौत हुई थी। लगातार मुर्गियों के मौत की घटना सामने आने के बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग की टीम ने सैंपल लिए है और जांच के लिए हिसार और सोनीपत भेजे गए है। बुधवार को मृत मुर्गियों के सैंपल क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला जालंधर भी भेजा गया है। गुरुवार को आरआरडीएल की दो टीमें बरवाला क्षेत्र में पहुंचकर नमूने लेने का काम शुरू कर दिया है। आरआरडीएल की टीम ने दो सैंपल लिए है, एक सैंपल को भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजा जाएगा। आशंका जताई है गयी है कि संदिग्ध बीमारियां रानीखेत या संक्रामक लारेंजो-ट्रैक्टिस हो सकती हैं।

### वायु प्रदूषण :मातृत्व सुख से वंचित हैं महिलायें

वायु प्रदूषण के चलते दक्षिण एशिया में हर साल साल 349,681 महिलाएं मातृत्व के सुख से वंचित रह जाती हैं। दक्षिण एशिया में हर साल साल 349,681 महिलाएं मातृत्व के सुख से वंचित रह जाती हैं, जोकि इस क्षेत्र में गर्भावस्था को होने वाले नुकसान का करीब 7.1 फीसदी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे में यदि इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को 40 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के स्तर पर सीमित कर लिए जाता है तो इन अजन्मों का जीवन बचाया जा सकता है।

# नये संकल्पों के साथ बीएयू में नव वर्ष मिलन समारोह मनायी गया

संवाददाता

***कुलपति ने आकस्मिक मजदूर, छात्र और पेंशन कर्मियों की समस्यायों का निदान पहली प्राथमिकता बताई कुलपति ने बिरसा किसान डायरी – 2021 व टेलीफोन डायरेक्टरी का विमोचन किया***

रांची : राजधानी रांची से सटे कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय मुख्यालय में नववर्ष के अवसर पर मिलन समारोह आयोजित किया गया. समारोह की शूरूआत बीएयू कुलगीत से हुई. मौके पर कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने विश्वविद्यालय कर्मियों को संबोधित करते हुए नववर्ष में अपनी प्राथमिकताएँ गिनाई. नये साल में नियमों के अधीन विश्वविद्यालय में कार्यरत मौसमी व गैर मौसमी आकस्मिक मजदूरों,अध्ययनरत छात्रों तथा पेंशन कर्मियों के समस्याओं के समाधान को पहली प्राथमिकता बताया. शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता तथा शिक्षकों को अग्रणी कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही. बीएयू से विकसित सभी तकनीकों / किस्मों / जानवरों की नस्लों वाली 'बास्केट ऑफ टेक्नोलॉजीज' नामक एक दस्तावेज अगले 3-4 महीनों में लाने तथा विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में 85% से अधिक किसान छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने की बात दोहराई. उन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तहत बीएयू कैंपस को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कैंपस बनाने का संकल्प जताया.

नववर्ष के अवसर पर विश्वविद्यालय में पहली बार कुलपति ने नवम्बर एवं दिसम्बर माह में सेवानिवृत्त कर्मियों में जेपी कन्दुलना, कैलाश उराँव, सेंद्रेल्ला लाकड़ा, सुशीला सिंह, बालकु महतो एवं अघनू महतो को भविष्य निधि राशि का चेक सौपा. मौके पर कुलपति ने निदेशालय प्रसार शिक्षा द्वारा प्रकाशित बिरसा किसान डायरी - 2021 व टेलीफोन डायरेक्टरी का विमोचन किया. निदेशक प्रशासन राकेश रौशन ने पदाधिकारियों एवं सभी विश्वविद्यालय कर्मियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय में बाधारहित वातावरण के लिए नियमों-परिनियमों का पालन और कुलपति के सकारात्मक प्रयासों में हर संभव सहयोग देने को कहा. डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉ जगरनाथ उराँव ने नए रूप रंग, कलेवर एवं अद्यतन कृषि तकनीकी से युक्त बिरसा किसान डायरी को प्रदेश के किसानों एवं कृषि से जुड़े लोगों के लिए उपयोगी बताया. समारोह का संचालन श्रीमती शशि सिंह ने की और धन्यवाद ज्ञापन रजिस्ट्रार डॉ नरेंद्र कुदादा ने दी। समारोह में विवि के डीन, डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, प्रोफेसर, टीचर, स्टाफ एवं आकस्मिक मजदूरों ने भारी संख्या में भाग लिया. समारोह का समापन राष्ट्र गान से किया गया।

## बीएयू की कृषि प्रसार समर्थित सेवाएँ

झारखण्ड प्रदेश में कृषि गतिविधियाँ बहुत हद तक मौसम एवं जलवायु पर निर्भर करती है. मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन का कृषिगत कार्यो तथा उत्पादन व उत्पादकता में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. बीएयू कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह बताते है कि कृषि जोखिम से बचाव के लिए भारत मौसम विभाग द्वारा मौसम की जानकारी नियमित प्रसारित की जाती है. इसके आधार पर सूचना सम्प्रेषण तकनीकों के माध्यम से विश्वविद्यालय के द्वारा अनेकों कृषि प्रसार समर्थित सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है. जिसकी जानकारी किसान पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से प्राप्त कर सकते है.

**पोर्टल** : विश्वविद्यालय के पोर्टल www.bau-eagriculture.com/weathar < http://www.bau-eagriculture.com/weathar> पर नागपुरी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध है. इस पोर्टल के मौसम पूर्वानुमान चित्र को क्लिक कर किसान अपने जिला, प्रखंड एवं पंचायत का दैनिक एवं घंटावार जानकारी प्राप्त कर सकते है.

**मोबाइल एप** : मौसम पूर्वानुमान एंड्राइड मोबाइल पर नागपुरी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है. गूगल प्ले स्टोर पर बिरसा वेदर सर्च कर किसान इस एप पर भाषा का चयन कर अपने इच्छानुसार जिला, प्रखंड एवं पंचायत का चयन कर दैनिक एवं घंटावार मौसम पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

कृषि प्रसार एवं संचार विभाग के वैज्ञानिक डॉ बीके झा ने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा कृषि प्रसार पर सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित कई अन्य सेवायें भी प्रदान की जा रही है। बहुभाषी समेकित पोर्टल : यह यूआरएल www.bau-eagriculture.com < http://www.bau-eagriculture.com> पर संथाली, नागपूरी, कुडुख, हो, मुंडारी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कृषि, पशुपालन एवं वानिकी से सबंधित विषय वस्तु पोर्टल पर उपलब्ध है।

**गाइडेड एसएमएस सेवा** : साधारण मोबाइल से प्राप्त की जा सकती है. इसके तहत विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एप को प्राप्त करनी होगी. इसके तहत संथाली, नागपूरी, कुडुख, हो, मुंडारी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कृषि, पशुपालन एवं वानिकी से सबंधित विषय वस्तु से सबंधित जानकारी एसएमएस सेवा से प्राप्त की जा सकती है.

**इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आई भीआरसी)** : यह हिंदी भाषा में विकसित किसान कॉल सेंटर है, जिसका दुरभाष संख्या 0651-2212001/18003457021 है, जो 24 घंटे कार्यरत रहता है. इसमें किसान सीधे किसानों से संपर्क कर सकते है. यह वॉयस मेल और एसएमएस सुविधा से युक्त है।

**लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (एलसीएमएस)** : इसमें बिना इन्टरनेट सूचना सम्प्रेषण हेतु स्थानीय भाषा में कृषि, पशुपालन एवं वानिकी से सबंधित विषय - वस्तु पर एलसीएमएस सीडी का विकास किया गया है।

**ई - डायरी** : किसानों के व्यापक हित में बिरसा किसान डायरी का ई वर्जन नागपुरी भाषा ऑनलाइन किया गया है, जिसे www.bau-eagriculture .com/birsakisandiary पर देखा जा सकता है।

**नागपुरी भाषा में आडियो बिरसा किसान डायरी** : स्थानीय किसानों की सुविधा हेतु बिरसा किसान डायरी को ध्वनी माध्यम में तैयार किया गया है, जो बीएयू एक्सटेंशन यूट्यूब चैनल के लिंक (https://www.youtube.com/playlist?list=PLs4F0IBVEd4vin-ShvvLTMyHoVkH7XKDv पर उपलब्ध है।

**बीएयू एक्सटेंशन यूट्यूब चैनल** : इस यूट्यूब चैनल पर नागपुरी भाषा में करीब 100 वीडियो उपलब्ध है।

## सीएमपीडीआई के सीएमडी ने अपने कर्मियों को जल शपथ दिलायी

रांची : 01 जनवरी राष्ट्रीय जल मिशन के उपलक्ष्य में सीएमपीडीआई के अध्यक्ष.सह.प्रबंध निदेशक एस0 सरन ने संस्थान के कर्मियों को जल शपथ दिलायी गयी। साथ ही नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर सीएमपीडीआई के निदेशक ;तकनीकी के0के0 मिश्रा निदेशक तकनीकी आरडीएंडटी आर0 एन0 झा निदेशक तकनीकी सीआरडी एस0 के0 गोमास्ता सहित महाप्रबंधक विभागाध्यक्षगण उपस्थित थे।

मौके पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एस0 सरन ने कहा कि बीता हुआ वर्ष यह साबित कर गया कि प्रकृति एवं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वैश्विक महामारी के कारण जहां एक ओर पूरा विश्व थम.सा गयाए वहीं प्रकृति अपने तरीके से पूरे वातावरण को स्वच्छ कर ली। महामारी के कारण आम लोगों को नयी.नयी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा किन्तु नयी-नयी तकनीकों के इस्तेमाल एवं संभावनाओं को तलाशने का मौका भी प्रदान किया। ऐसी त्रासदी एक शताब्दी में कभी.कभार देखने एवं सुनने को मिलती है और यह सब हमारे जीवन में देखने एवं सहने को मिला है। श्री सरन ने कहा कि यह न सिर्फ नए वर्ष की शुरूआत है बल्कि नए दशक का आगाज है। आशा करता हूं कि यह वर्ष और दशक कोयला उद्योग समेत सीएमपीडीआई के लिए मंगलमय होगा। उन्होंने सीएमपीडीआई में कार्यरत सभी कर्मियों एवं उनके परिवार के लिए सुखए समृद्धि एवं बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर सीएमपीडीआई के निदेशक तकनीकी के0के0 मिश्रा ने कहा कि बीते वर्ष बहुत ही कष्टकारी किन्तु सीख देने वाला वर्ष रहा है। निदेशक तकनीकी आरडीएंडटी आर0एन0 झा ने सभी कर्मियों के लिए सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। निदेशक तकनीकी एस0 के0 गोमास्ता ने कहा कि गत वर्ष त्रासदी भरा रहा किन्तु हम सब के जीवन में बहुत कुछ सबक भी दे गया है। गोमास्ता ने सभी कर्मियों के लिए मंगल कामना की।

### सीएमपीडीआई परिवार के 6 सदस्यों को सम्मानित किया गया

रांची : सीएमपीडीआई परिवार के 6 सदस्यों को संस्थान के ''कांफ्रेंस हॉल'' में आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। इनमें एस0सी0 जोशी- महाप्रबंधक (सिस्टम), उत्पल चक्रवर्ती-महाप्रबंधक (ईएंडएम), श्री किशोर कुमार-महाप्रबंधक (ईएंडएम), समीर विश्वास-मुख्य प्रारूपक, शंभु प्रसाद-इंजीनियरिंग सहायक एवं बी0के0 सिन्हा-मुख्य भंडारपाल शामिल हैं। इस मौके पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन एवं निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) एस0 के0 गोमास्ता ने सेवानिवृत्त कर्मियों को पुष्पगुच्छ, मान-पत्र, प्रतीक चिह्न व शॉल देकर कम्पनी की ओर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन एवं निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) एस0 के0 गोमास्ता ने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। महाप्रबंधक (गवेषण) श्री ए0के0 पांडा, महाप्रबंधक (ईएंडएम) ए0के0 सिंह, महाप्रबंधक एस0सी0 प्रसाद, महाप्रबंधक बी0 श्रीनिवासु, श्रमिक प्रतिनिधि श्री निताय घोष एवं सर्वेश प्रसाद ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए।मंच का संचालन प्रबंधक नवीन कुमार सिन्हा व धन्यवाद ज्ञापन वरीय प्रबंधक रासबिहारी ने किया।

## सीसीएल में सेवानिवृत कर्मियों को भावभीनी विदाई

संवाददाता

सीसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों सर्वश्री विजय कुमार, महाप्रबंधक (कर्मचारी स्थापना), कर्मचारी स्थापना विभाग; सुभांकर गांधी, मुख्य प्रबंधक (ई. एण्ड एम.),एनआईएमसी विभाग; सुवेन्दु नारायण भट्ट, मुख्य प्रबंधक (वित्त), एमएम विभाग; मदन मोहन मिश्रा, वरीय निजी सहायक 'ए-1', एमएम विभाग; बिनोद कुमार विश्वकर्मा, एकाउंटेंट 'ए-1', पे रोल विभाग को सीसीएल परिवार की ओर से सीसीएल मुख्यालय में ''सम्मान समारोह'' का आयोजन कर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल सहित महाप्रबंधक (पी. एंड आई.आर.) उमेश सिंह;

महाप्रबंधक (अधिकारी स्थापना) ए.के. सिंह, महाप्रबंधक (सामाजिक सुरक्षा) यू.पी. नारायण, महाप्रबंधक (सुरक्षा व बचाव) एस.वी. मराठे एवं अन्य सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये उपस्थित थे। महाप्रबंधक (कल्याण) डॉ. ए.के. सिंह ने समारोह के मुख्य आकर्षण सेवानिवृत कर्मियों को कंपनी की ओर से स्वागत किया और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये उन्हें सेवानिवृत बेनिफिट प्रदान किया गया। सीसीएल द्वारा कोरोना महामारी के समय नया प्रयास करते हुये सेवानिवृत कर्मियों पर फिल्म निर्माण किया गया जिसमें सभी सेवानिवृत कर्मियों ने अपना- अपना विचार व्यक्त किये और सम्मान समारोह के अवसर पर यह फिल्म दिखाया गया। फिल्म के दौरान सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने पूरे सीसीएल परिवार में सेवानिवृत कर्मियों को संबोधित करते हुये कहा कि आप सभी हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे, इस दिशा में कंपनी के सोशल मीडिया के माध्यम से कंपनी के विभिन्न गतिविधियों के बारे में नवीनतम जानकारी के साथ जुड़े रह सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक (कल्याण) डॉ. ए.के. सिंह ने किया। सम्मान समारोह को सफल बनाने में कल्याण विभाग के कर्मियों का विशेष योगदान रहा।

# पंचायत में हम सबों को जागरूक होना होगा: राजेन्द्र शाही मुंडा

रांची संवाददाता : दिनांक 3 जनवरी को अंगारा पचंयात में मिलन समारोह का आयोजन नेशनल फोरम आफ एससी/एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटी के तत्वावधान में कुच्चु पंचायत भवन में किया गया। पंचायत प्रमुख राजेन्द्र शाही मुंडा ने नेशनल फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सहदेव राम एवं अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। इस आयोजन में नेशनल फोरम की ओर से सभी मुखिया, मानकी, पंचायत समिति के प्रतिनिधि,आंगनबाड़ी सेविकाओं और किसानों का स्वागत किया गया।

मिलन समारोह की अध्यक्षता प्रमुख राजेन्द्र शाही मुंडा ने किया । उन्होंने ग्राम पंचायत के समस्त मुखिया, ग्राम प्रधान, पंचायत समिति , जिला परिषद् शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये कहा कि पंचायत का महत्व रामायण और महाभारत काल में भी था इसका जिक्र वेदों में भी है। किन्तु 1786 में ब्रिटिश संसद ने गावों की व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की किन्तु खुद 1830 में पुनः इसे आवश्यक बताते हुये कायम रखा। आजादी के बाद राजस्थान पहला राज्य बना जहां पर पंचायत राज्य व्यवस्था को लागु किया गया। बाद में सभी राज्यों में इसे लागु किया गया।वर्तमान में तीन लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में पचास। प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। किंतु संविधान में जितना अधिकार दिया गया है उसका न तो पालन किया जा रहा है न जनता उसका महत्व समझती है। इसके लिये हम सबों को जागरूक होने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुये डॉ.० राम ने कहा कि झारखंड सरकार की भूमिका वर्तमान में बहुत अहम मानी जा रही है। क्योकि कोरोना काल में अन्य राज्यों से

लौटे छह लाख से अधिक मजदूरों के लिये रोजगार की घोषणा सरकार ने 4 मई 2020 को किया गया था। इस-के बाद भी राज्य में बेरोजगारी दर 47.1 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगुना है। झारखंड देश का सबसे धनी राज्य है फिर भी यहां के लोग बेरोजगार हैं भुखमरी और विस्थाप के शिकार हैं। सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या में गिरावट आ रही है। सरकार ने 11843.24 करोड़ की लागत से 8228 योजनाओं का शुभारंभ किया है तो यह गांव के सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसका लाभ आखिरी व्यक्ति को मिले। इसके लिये हम सबको मिल कर काम करना होगा। राज्य को तीन बातें कमजोर कर रही है। नशा, बाल विवाह और दहेज प्रथा। इस पर हमें काबू पाना होगा। आयोजन के मुख्य वक्ताओं में राजेन्द्र शाही मुंडा, मुखिया संगीता देवी, सभानंद बेदिया, रमाकांत शाही, राजेश पहान, जय शंकर पहान, भुनेश्वर बेदिया, बालेश्वर बेदिया, सीतानाथ पातरनाथ मुंडा, डॉ. परमेश्वर लाल, प्रोफेसर रिझु नायक, दिलीप मिर्धा, सिकंदर मुंडा नेशनल फोरम के वरीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सिविल सर्जन डॉ. शिव शंकर , महासचिव सुरेन कुमार, अधिवक्ता नसीम अख्तर, राजकुमार रविदास के साथ कार्यकारिणी के अनय सदस्य उपस्थित थे। सभा का संचालन श्रवण मुख्तियार तथा हेमंत नायक ने किया। सभी ने सामाजिक दूरी बना कर कार्यक्रम को सफल बनाया।

# बहुत बड़ी है प्रदूषण की आर्थिक कीमत

एजेंसियां

देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर पाने में नाकामी हाथ लगने के कारण देश को हर वर्ष 37 अरब डॉलर मूल्य की आर्थिक क्षति पहुंच रही है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 1.4 प्रतिशत है। इतना ही नहीं करीब 16.7 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषित हवा के चलते अपनी जान गंवा बैठते हैं। मौत का यह आंकड़ा दुनिया में सर्वाधिक है और यहां तक कि यह कोविड-19 के कारण हुई मौतों से भी ज्यादा है। आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी तथा उत्पादकता संबंधी यह क्षति देश की तेज आर्थिक वृद्धि की आकांक्षा की राह रोक सकती है। ये चौंकाने वाले खुलासे स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका द लैंसेट में प्रकाशित किए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि वायु प्रदूषण की समस्या से सही ढंग से नहीं निपटा गया तो यह हमारे बच्चों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत बुरा होगा। आने वाली पीढ़ियों में हृदय रोग, मधुमेह और श्वसन संबंधी बीमारियों की आशंका अधिक होगी। यहां तक कि बच्चों की बुद्धिमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद वायु प्रदूषण से लड़ाई हमारी प्राथमिकता में नहीं है।

अंदाजा लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण की समस्या के लिए उत्तर भारत के भारी प्रदूषण वाले राज्य अधिक जवाबदेह हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) इसका गढ़ है। इस समूचे क्षेत्र में व्याप्त हवा वर्ष भर अत्यधिक प्रदूषित रहती है और ठंड के दिनों में तो हालात अत्यधिक खराब

हो जाते हैं। यही वह समय है जब स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 और पीएम10 समेत तमाम प्रदूषक तत्त्व जमीन के करीब रहते हैं और हमारे इर्दगिर्द की हवा में मिलकर दमघोंटू माहौल बना देते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में एनसीआर के आसपास के इलाकों में फसल अवशेष जलाए जाते हैं जिससे धुआं तथा अन्य प्रदूषक तत्त्व उत्पन्न होते हैं। इससे इस इलाके की हवा और प्रदूषित हो जाती है। परंतु स्थानीय कारक मसलन धूल, वाहनों से होने वाले प्रदूषण और कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

चूंकि प्रदूषण के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है इसलिए भारत को विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण नीतियां तैयार करने की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार के कुछ हालिया कदम बेहतर नजर आते हैं।

सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में हवा की गुणवत्ता का प्रबंधन करने के लिए अधिकारप्राप्त आयोग की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) तथा इसके तहत तीन अन्य समितियों और कार्यबल की नियुक्ति की है। लेकिन हकीकत में गत 5 नवंबर को एक अध्यादेश द्वारा गठित यह आयोग युद्ध स्तर पर काम करने में नाकाम नजर आया है। अब तक कुछ सामान्य आदेश जारी किए गए हैं। इसमें भी पानी की फुहारेदार सिंचाई, सड़कों पर यांत्रिक तरीके से झाड़ू लगाने और विनिर्माण और इमारतों को ध्वस्त करने पर धूल को नियंत्रित रखने जैसे आदेश प्रायः कागजों पर ही रह गए। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में इस इलाके की हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब रही है। हवा को साफ करने के लिए जिस प्रकार के आपात उपायों की आवश्यकता थी वे देखने को नहीं मिले हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आश्चर्य जताया है कि यदि ऐसा ही होना है तो हर राज्य की भागीदारी वाली इतनी बड़ी संस्था का गठन क्यों किया गया। आयोग अपनी प्रासंगिकता तभी साबित कर पाएगा जब वह नए विचार पेश करता है और प्रदूषण के स्रोत पर रोक लगा सकता है। केवल पुराने कदमों को दोहराने से सफलता नहीं मिलेगी।

# फोटो न्यूज

## गाय के लिये मच्छरदानी

## कंक्रीट जंगल पतंग उड़ाने लायक आकाश भी नहीं छोड़ेगा

# कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल

***सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने कोयला आधारित बिजली खरीद का राज्यवार आकलन और विश्लेषण किया है***

**अनिल शर्मा**

प्रदूषित कोयला खरीद कर बिजली उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल देश में पहले स्थान पर है। इसका मतलब है कि यह राज्य सबसे अधिक कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जित कर के मामले में देश में पहले पर नंबर है। यह खुलासा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने किया है। सीएसई ने कोयला आधारित बिजली खरीद का राज्यवार आकलन और विश्लेषण किया और इसमें पाया कि पश्चिम बंगाल सल्फर के अनुपालन में देश में सबसे फिसड्डी राज्य है और प्रदूषित कोयला खरीद कर बिजली उत्पादन में नंबर एक राज्य है। सीएसई द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में बिजली की आपूर्ति करने वाले अधिकांश स्टेशनों ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिसंबर, 2015 के सल्फर डाइऑक्साइड मानदंडों के अनुपालन के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं। इस संबंध में सीएसई के औद्योगिक प्रदूषण कार्यक्रम के निदेशक निवित कुमार यादव कहते हैं, ''कोयला आधारित बिजली स्टेशनों में तीन प्रमुख प्रदूषक हैं- कण पदार्थ, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पावर स्टेशन सल्फर डाइऑक्साइड मानदंड के अनुपालन में विशेष रूप से पिछड़ गए हैं। ध्यान रहे कि पहले से ही सल्फर डाई आक्साइड के मानदंडों को कमजोर करने के लिए दबाव बना हुआ है। दिसंबर, 2015 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कण पदार्थ, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक निश्चत मानदंड निर्धारित किया हुआ है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय इस मानदंड में और छूट देने की मांग कर रहा है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिजली संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारत में आधे से अधिक मानवजनित उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। सीएसई ने अपने मूल्यांकन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके बिजली उत्पादन के प्रतिशत के आधार पर श्रेणी प्रदान की है। 33 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से ही बिजली खरीदी जाती है। इन राज्यों के पास विभिन्न कोयला-फायरिंग पावर जनरेटर के साथ टाई-अप है जो विभिन्न राज्यों में भी स्थित हैं। सीएसई ने बिजली मंत्रालय की वेबसाइट से आंकड़ों को लेकर आकलन किया है कि किसी विशेष राज्य द्वारा कितनी क्लीन बिजली खरीदी जा रही है। सीएसई ने अपने अध्ययन में पाया कि देश के नौ राज्य प्रमुख रूप से सरकारी मापदंडों को पालन में चूक कर रहे हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य अपनी कोयले पर आधारित बिजली का लगभग 60 प्रतिशत अशुद्ध स्रोतों से खरीद रहे हैं। इस मामले में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात शीर्ष पर हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य को बिजली की आपूर्ति करने वाले 84 प्रतिशत बिजली स्टेशन अशुद्ध हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के मानदंडों को पूरा करने से बहुत दूर हैं।

पश्चिम बंगाल अपने बिजली स्टेशनों के माध्यम से अपनी जरूरत की सभी बिजली उत्पन्न करता है। इसलिए राज्य में नियामक अधिकारियों के पास प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक शक्तियां हैं। तेलंगाना में यह आंकड़ा 74 प्रतिशत है और गुजरात में यह 71 फीसदी है। इन राज्यों में स्थित और आपूर्ति करने वाले अधिकांश पावर स्टेशनों ने मानदंडों को बहुत कम पूरा किया है।

## अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को मजबूत करेंगे बाइडेन

एजेंसियां: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण एजेंसी यानी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए कमर कसी है। यह एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप के शासन काल में पूरी तरह से पटरी से उतर गई थी। ध्यान रहे कि ट्रंप प्रशासन ने जलवायु परिवर्तन को पूरी तरह से मानने से इंकार कर दिया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ट्रंप प्रशासन ने इस एजेंसी को पूरी तरह से न केवल नकार दिया था बल्कि एजेंसी के वैज्ञानिकों की बातों को पूरी तरह से अपने शासन काल के दोरान खारिज कर दिया था।

इतना ही नहीं, एजेंसी के वैज्ञानिकों के मनोबल को भी पूरी तरह से तोड़ने की हर संभव कोशिश ट्रंप प्रशासन द्वारा की की गई थी। लेकिन अब नए राष्ट्रपति ने जिस प्रकार से अनुभवी पर्यावरण विनियामक( रेगुलेटर) माइकल रेगन को ईपीए के प्रमुख पद पर नियुक्त किया है, इससे दुनियाभर के वैज्ञानिकों की आशा बलवती हो चली है कि बाइडन प्रशासन हर हाल में जलवायु परिवर्तन के लिए कटिबद्ध है और भविष्य में भी रहेगा। बाइडन के इस कदम से अमेरिका सहित पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के बीच विश्वास बढ़ा है।

ध्यान रहे कि माइकल रेगन पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत नागरिक होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने देश के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए उत्तरी कैरोलिना के शीर्ष पर्यावरण नियामक माइकल रेगन को नामित किया है। रेगन की नियुक्त के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या बाइडन के इस कदम से उनके अपने क्रांतिकारी जलवायु परिवर्तन के एजेंडे के नतीजे और कितने प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होंगे।

# बिहार और मेघालय की 40 फीसदी से कम आबादी कर रही है स्वच्छ ईंधन का उपयोग

देश में उज्ज्वला की सफलता के बावजूद बिहार और मेघालय जैसे राज्यों की बड़ी आबादी आज भी खाना पकाने के लिए एलपीजी और अन्य स्वच्छ ईंधनों की पहुंच से दूर है। आज भी देश में बिहार और मेघालय जैसे राज्यों में 60 फीसदी से ज्यादा घरों में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग नहीं होता।यह जानकारी हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 (एनएफएचएस -5) में सामने आई है।देश में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यदि घरों में लकड़ी, कोयला या गोबर को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदूषण में इजाफा करता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है।यदि आंकड़ों पर गौर करें तो मेघालय के केवल 33.7 फीसदी घरों में साफ़ ईंधन का उपयोग किया जा रहा है।यही स्थिति बिहार की भी है जहां सिर्फ 37.8 फीसदी घरों में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग किया जा रहा है

हालांकि "स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ केंद्र सरकार नें 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना शुरू की थी।सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक इस योजना के तहत गरीब तबके को रियायती दर पर करीब 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।जिसके बाद स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर आया है।देश में सिर्फ गोवा (96.5) और तेलंगाना (91.8) की 90 फीसदी से ज्यादा आबादी स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर रही है। यदि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अब भी बदतर है।जहां पश्चिम बंगाल की केवल 20.5 फीसदी आबादी स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर रही है।वहीं मेघालय (21.7), बिहार (30.3), नागालैंड (24.9), त्रिपुरा (32.6), असम (33.7), लक्षद्वीप (24.7), हिमाचल प्रदेश (44.5) और गुजरात (46.1) की स्थिति भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है

# सदी के अंत तक 3 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगी तापमान में हो रही वृद्धिः एमिशन गैप रिपोर्ट

एजेंसियां

रिपोर्ट के अनुसार महामारी से आई आर्थिक मंदी के चलते 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में करीब 7 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है

यूएन द्वारा प्रकाशित "एमिशन गैप रिपोर्ट 2020" से पता चला है कि यदि तापमान में हो रही वृद्धि इसी तरह जारी रहती है, तो सदी के अंत तक यह वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस के पार चली जाएगी। जिसके विनाशकारी परिणाम झेलने होंगे। तापमान में आ रही इस वृद्धि का सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर भी पड़ेगा। बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाओं का आना आम बात हो जाएगा। जिसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा। जहां एक तरफ यह आपदाएं उनके जीवन पर असर डालेंगी वहीं दूसरी तरफ यह कृषि पर भी असर करेंगी जिसका असर आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 और उसके कारण आए ठहराव के चलते उत्सर्जन में कुछ कमी आई थी पर वो कमी लम्बे समय तक नहीं रहेगी।

रिपोर्ट का मानना है कि महामारी से आई आर्थिक मंदी के चलते 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 7 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि यह कमी पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने में कोई ज्यादा मदद नहीं करेगी। अनुमान है कि 2020 में उत्सर्जन में जो कमी आई है, उसके चलते 2050 तक तापमान में सिर्फ 0.01 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ऐसे में यदि महामारी का फायदा उठाना है तो इस आर्थिक मंदी से उबरते वक्त पर्यावरण और क्लाइमेट को भी ध्यान में रखना होगा, इस महामारी ने हमें एक ऐसा मौका भी दिया है जिसका लाभ उठाकर हम अपने उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं और आने वाले वक्त में 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।

लगातार तीसरे साल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की गई है। जो 2019 में बढ़कर अब तक के 59.1 गीगाटन (ग्रीन हाउस गैस + भूमि उपयोग में आया परिवर्तन) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। जबकि 2010 से उत्सर्जन में औसतन 1.4 फीसदी की दर से वृद्धि हो रही थी, जो 2019 में बढ़कर 2.6 फीसदी पर पहुंच चुकी है। भारत में 2010 से 19 के बीच 3.3 फीसदी की दर से उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की गई है। यदि भारत के उत्सर्जन को देखें तो 2019 के दौरान भारत में 3.7 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ था। इस आधार पर भारत, चीन (14 गीगाटन), अमेरिका (6.6 गीगाटन) और यूरोप और यूके (4.3 गीगाटन) के बाद चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। जबकि यदि भारत में प्रति व्यक्ति द्वारा किए जा रहे उत्सर्जन पर गौर करें तो यह 2.7 टन सीओ2इ प्रति व्यक्ति है, जोकि अंतराष्ट्रीय औसत (6.8 टन सीओ2 प्रतिव्यक्ति) से भी काफी कम है।

साथ ही यह चीन (9.7 टन सीओ2इ प्रतिव्यक्ति), अमेरिका (20 टन सीओ2इ प्रतिव्यक्ति), यूरोप और यूके (8.6 टन सीओ2इ प्रतिव्यक्ति), रूस (17.4 टन सीओ2इ प्रतिव्यक्ति) और जापान (10.7 टन सीओ2इ प्रतिव्यक्ति) से भी कई गुना कम है। यदि भारत द्वारा 2010 के बाद से किए जा रहे उत्सर्जन की बात करें यह हर वर्ष औसतन 3.3 फीसदी की दर से बढ़ रहा था। जबकि 2019 में उत्सर्जन की दर में कमी दर्ज की गई है जब इसमें हो रही वृद्धि 1.3 फीसदी दर्ज की गई थी।

भारत अपने उत्सर्जन में कमी करने के लिए कई प्रयास कर रहा है इसी दिशा में उसने 2020 के पहले छमाही में कोई थर्मल पावर प्लांट स्थापित नहीं किया है।

# सूखती बूढ़ा नदी से भेड़ियों के अभ्यारण्य पर खतरा

.....पेज एक का शेष

हालांकि, वर्ष 2018 में खनन का काम रुक गया। इसकी वजह थी भेड़िया अभयारण्य के आसपास के इलाके को इको सेंसेटिव जोन में शामिल करने संबंधित नोटिफिकेशन का जारी होना। वर्ष 2019 में इस इलाके को इको सेंसेटिव जोन में शामिल भी कर लिया गया। जिन स्थानीय लोगों के प्रयास से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा, वे अब भी संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि झारखंड में इसका खनन तो रुक गया, लेकिन इनके क्षेत्र से सटे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में खनन अब भी जारी है।

**बॉक्साइट खनन की वजह से बुरहा नदी की धार धीमी हो रही है**

बॉक्साइट खनन की वजह से बुरहा नदी की धार धीमी हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची से 194 किलोमीटर दूर स्थित लातेहार का यह भेड़िया अभयारण्य 90 भेड़ियों का घर है। इसके अलावा यहां भालू और तेंदुए की अच्छी खासी आबादी भी रहती है।

झारखंड की सामाजिक कार्यकर्ता शशि पन्ना ने बताया कि इको सेंसेटिव जोन का निर्णय झारखंड तक ही सीमित था, जिसकी वजह से यहां खनन तो रुक गया, लेकिन इलाके से सटे छत्तीसगढ़ में यह जारी है। ''छत्तीसगढ़ में हिंडाल्को का खदान 3,741 एकड़ में फैला हुआ है।झारखंड के वन्यप्राणी विशेषज्ञ डीएस श्रीवास्तव बताते हैं कि यह मामला दो राज्यों के बीच का है इसलिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए।

खनन की वजह से छत्तीसगढ़ से निकलकर झारखंड के पलामु टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली बुढा नदी की धार भी धीमी हो रही है। इसकी बड़ी वजह नदी के कैचमेंट एरिया में बने खदान को माना जाता है। इस रिजर्व से 64 किलोमीटर दूर भेड़िया अभयारण्य है।ओरसा गांव के वकील अहमद के मुताबिक बुरहा नदी को खदानों से खतरा है। इनका आरोप है कि बॉक्साइट खनन के बाद खदान को खुला छोड़ दिया गया। वर्ष 2018 में पलामु टाइगर रिजर्व ने बॉक्साइट खदानों को रिजर्व के लिए खतरा बताते हुए छत्तीसगढ़ वन विभाग को पत्र लिखा था। तत्कालीन अधिकारी महालिंगा ने बताया कि उन्होंने पत्र में बुढ़ा नदी के कैचमेंट में हो रहे खनन और उससे नदी पर हो रहे विपरीत प्रभावों के बारे में बताया था। वकील अहमद कहते हैं कि ओरसा से गुजरने वाली इस नदी में अगर पानी खत्म हो गया तो यहां के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। जमीन के भीतर इतना पानी नहीं कि लोग लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकें। छत्तीसगढ़ में खनन जारी रहने की वजह से बुरहा नदी पर बने पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण झरनों को नुकसान हो रहा है। हाल के वर्षों में पानी में काफी कमी देखी जा रही है। नदी में पानी कम हुआ है और अब यह पानी प्रदूषित भी है। जंगल के आसपास अब जंगली जानवर भी नहीं दिखते। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के पूर्व वन अधिकारी विवेकानंद झा कहते हैं कि टाइगर रिजर्व से पत्र मिलने के बाद उन्होंने अधिकारियों को मामले की जांच के लिए कहा था, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से जांच में देरी हो रही है। बलरामपुर में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का एक 257 हेक्टेयर में फैला खदान है जो कि भेड़िया अभयारण्य से 10 किलोमीटर दूर है। इस खदान के प्रभाव को लेकर भी चिंताए जताई जाती रही हैं।

**खनन बंद होने के बाद भी समस्याएं खत्म नहीं हुईं**

इको सेंसटिव जोन बनने के बाद ओरसा में खनन का काम रुक गया है। हालांकि, यहां के लोगों की परेशानी अब भी बनी हुई है। स्थानीय निवासी सुनिता नगेसिया और दुलारी देवी कहती हैं कि खदान के गड्ढे में गिरकर उनके कई जानवर मर चुके हैं। उन्हें अपने खेतों तक जाने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ता है।

**खदान को समतल करने की मांग कर रहे हैं, ग्रामीण**

तातिझारिया गांव से पास बने खदान से धूल की काफी मात्रा निकलती है। धूल से कई किलोमीटर के दायरे में खेती चौपट है। छत्तीसगढ़ के खदानों के आसपास रहने वाले लोगों को भी कई तरह की परेशानियां हो रही है। तातिझारिया गांव खदान से पांच किलोमीटर दूर है, लेकिन धूल की वजह से यहां के फसलों पर इसका असर हो रहा है। इस गांव के अनिल यादव और राकेश सिंह के मुताबिक गांव के पास खदान एक दशक से अधिक से चल रहे हैं। ''ब्लास्ट की वजह से धूल का गुबार उठता है, जो खेतों में खड़ी फसल पर बैठ जाता है,'' वे कहते हैं गांव के लोगों ने शिकायत की कि हिंडाल्को ने खनन के बाद जंगल लगाने का काम ठीक से नहीं किया। वहीं हिंडाल्को का दावा इसके विपरीत है। बलरामपुर कलेक्टर ने बताया कि अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है।

# देश ऐसा बने कि युवा नौकरी खोजने वाला नहीं देने वाला हो

**संवाददाता**

***झारखंड के युवा उद्यमी और हमेंशा ऊर्जा से सराबोर रहने वाले रंथिन भद्रा जिन्होंने भुंगरू तकनीक के माध्यम से जल संचयन में क्रांति ला दी है। उन्होंने हाल ही में रांची में अपने सहयोगियों के साथ एक कार्यक्रम में अपने विचार रखे जिसे हम हु-बहू प्रकाशित कर रहे हैं।***

Indian startup association झारखंड के युवा उद्यमियों द्वारा स्थापित किया गया एक non profit organization है जो नए उद्यम, स्टार्टअप के लिए एक मंच स्थापित करने उद्देश्य से बनाया गया है। क्श्वअ का मुख्य उद्देश्य झारखंड और देश के सभी युवा उद्यमियों को उनके व्यवसाय, वित्त और विकास संबंधी सहायता प्रदान करना तथा राज्य और भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप्स के लिए बनाई गई योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना है।

वर्तमान समय मे जब सारी दुनिया इस वैश्विक महामारी से जूझ रही है, और सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, उसमे आशा की किरण सिर्फ और सिर्फ रोजगार के ढेरों अवसर पैदा करके ही किया जा सकता है। इस विषय से संबंधित एक सुझाव साझा करना चाहता हूँ, जिस पर ध्यानाकर्षित करने पर निश्चित तौर पर झारखंड में भी ढेर सारे रोजगार के अवसर बनेंगे जो कि राज्य को समृद्ध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

केंद्र सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में हमारे राज्य में झारखंड स्टार्टअप पालिसी बनाई गई, जिसपर तत्कालीन सरकार ने कई सकारात्मक काम भी किये, और इस योजना के तहत ढेर सारे स्टार्टअप्स का चयन भी किया गया। IIM तथा झारखंड के IT डिपार्टमेंट के सहयोग से झारखंड इनोवेशन लैब ( अब अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब) की स्थापना भी की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सारे चयनित स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन, वित्तपोषण,कानूनी सहित स्टार्टअप्स के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करने संबंधित विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना था। साथ ही और भी कई प्रकार की सुविधाएं मिलने का वादा किया गया था। 10/04/2019 तत्कालीन मुख्य सचिव डी के तिवारी के द्वारा जारी गए पत्र संख्या 376/35 का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में स्टार्टअप्स को मौका देने की बात कही गयी थी, लेकिन वर्तमान में ये योजना भी धरातल पर नही उतर सका। इसमे चयनित स्टार्टअप्स में से कुछ को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास जी के हाथों प्रमाणपत्र तथा वितीय सहायता का कुछ अंश जरूर प्रदान किया गया। किन्तु, मौजूदा समय में ये सारे स्टार्टअप अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ सही दिशा, परामर्श और वितीय सहायता न मिलने के कारण निराश होकर बन्द हो चुकने के कगार पर हैं। रही सही कसर कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न हालात ने पूरी कर दी है। किन्तु, अभी भी निश्चित तौर पर ढेर सारी संभावनाएं बची हैं। आवश्यकता है की इन्हें प्रोत्साहित किया जाए और इन्हें सही दिशा और गति देने का प्रयास किया जाए क्योंकि, इस समस्या के हल होने से न सिर्फ रोजगार से संबंधित कई बड़ी समस्याओं का निदान संभव है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था तथा कई प्रकार के नवीनतम उद्योग का भी सृजन होने की संभावना है।

करीब 110 स्टार्टअप्स, जो कि कृषि, अनुसंधान, विज्ञान, प्राद्योगिकी और व्यवसाय सहित विभिन्न प्रकार के नवीनतम विचार पर शोधरत हैं, के पास 100000 से भी ज्यादा लोगो को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार देने की संभावना है। जरूरत सिर्फ इस बात की है, कि इस योजना से जुड़े सारे स्टार्टअप को साधन और संसाधन मुहैया कराया जाए तथा व्यापक स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसे सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए। इसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता भी नही है, बल्कि जो पहले से चली आ रही योजना है, उसे जमीनी स्तर पर उतारने की आवश्यकता है। आज के मौजूदा हालात में जब सरकार अनेक प्रकार की नवीनतम योजनाए ला रही है, ताकि इन प्रवासी मजदूरों को उन्हें उनके घर मे रोजगार मिल सके, राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके तो ऐसी परिस्थिति में स्टार्टअप्स एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। बस उन्हें सही दिशा देने, प्रोत्साहित करने तथा इससे संबंधित लोगों को इस विषय की ओर ध्यानाकर्षित करने की आवश्यकता है।

इंडियन स्टार्टअप एसोसिएसन का मुख्य उद्देश्य सरकार और स्टार्टअप्स के बीच की इस खाई को पाटना और स्टार्टअप्स की बेहतरी के लिए काम करना है, जिसमे स्टार्टअप्स को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान में झारखंड से शुरू होकर इस संगठन का विस्तार भारत के विभिन्न राज्यों तक शुरू हो चुका है, जिसमे देश के विभिन्न स्टार्टअप्स जुड़ रहे हैं। हम एक ऐसे भारत के निर्माण पर कार्य कर रहे हैं जहां का युवा नौकरी खोजने वाला नही बल्कि देने वाला बने।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in

Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511

Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm

SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी )आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।